प्रेस विज्ञप्ति

24 अगस्त, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया:–

भारत की 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से गंभीर समझौता करते हुए 22,400 पेजों के 'प्रोजेक्ट 75' के साथ 'Scorpene पनडुब्बियों' की पूरी डिज़ाईन योजना एवं विवरणों को लीक कर दिया गया है। लीक हुए इन दस्तावेजों पर भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। वर्तमान समय की यह सबसे बड़ी रक्षा आपदा है। यह शर्मनाक लीक भारत की तटीय सुरक्षा को कटघरे में खड़ा करता है और फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस की छः Scorpene पनडुब्बियों के निर्माण कार्य को खतरे में डालता है, जो 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 23,500 करोड़ रु.) के खर्च पर माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लि. के द्वारा बनाई जा रही हैं।

Scorpene पनडुब्बियों के विवरण के चिंताजनक लीक में शामिल हैं : (i) 4301 pages of Combat Management System and 493 pages of specifications of Torpedo Launch System; (ii) Secret stealth capabilities of the 6 submarines; (iii) 4457 pages of submarine's underwater sensors & 4209 pages of submarine's above water sensors; (iv) 6841 pages of submarine's communication systems; (v) Diving depth, range and endurance; (vi) Magnetic, electromagnetic and infra red data; (vii) Frequencies at which they gather intelligence; (viii) Details of speed & conditions needed for using the periscope; (ix) Noise specifications of the propeller; (x) Radiated noise levels that occur when submarine surfaces; (xi) Level of noise at various speeds; (xii) Places where submarine crew can speak to avoid detection.

भारत की रक्षा तैयारी को गहरी चोट पहुंचाने वाली इस बड़ी भूल के बावजूद, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार एवं रक्षा मंत्री, श्री मनोहर पार्रिकर जिम्मेदारी तय करने की बजाए इस जबरदस्त नाकामी को दबाने में लगे हैं। चिंता की बात यह है कि रक्षामंत्री एवं भारतीय नौसेना अलग अलग बातें कर रहे हैं। श्री पार्रिकर, जहां इन लीक्स को 'हैकिंग' बता रहे हैं, वहीं भारतीय नौसेना कह रही है कि 'इन लीक्स का स्रोत विदेशों में है, भारत में नहीं'। सरकार अपनी इस असफलता को छिपाने के लिए यह तक कह रही है कि ये लीक 'पुरानी जानकारी' के हैं और इससे होने वाला नुकसान बहुत छोटा है एवं ऑपरेशनल क्षमताओं से कोई भी समझौता नहीं किया गया है।

दूसरी तरफ, फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस ने ऑस्ट्रेलिया को फूल प्रूफ सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए साफ संकेत दिया है कि यह लीक भारत में ही हुआ होगा क्योंकि डीसीएनएस में डेटा का अनधिकृत एक्सेस रोकने के लिए विभिन्न एवं स्वतंत्र कंट्रोल हैं और सभी डेटा मूवमेंट्स एनक्रिप्टेड एवं रिकॉर्डेड हैं। भारत में जहां डीसीएनएस डिज़ाईन एक स्थानीय

कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए डीसीएनएस तकनीकी डेटा का प्रदाता है, न कि नियंत्रक।

चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा विवरण ऑनलाईन अपलोड तक कर दिया गया, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी की सरकार एवं रक्षा मंत्री दोषारोपण करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटीय रेखा की रक्षा के लिए महज 13 पनडुब्बियों एवं एक न्यूक्लियर पनडुब्बी के साथ लगता है कि सरकार भ्रम में जी रही है।

इस बड़ी गलती के लिए माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई एवं डिफेंस मंत्रालय का संपूर्ण 'सुरक्षा ऑडिट' किया जाना चाहिए। सुरक्षा ऑडिट/जांच आयोग ही लीक के स्रोत का पता लगा सकेगा, जो रक्षामंत्री या भारतीय नौसेना द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर नहीं किया जा सकता है। यह बात चिंताजनक है कि एक उचित जांच किए बिना ही किस प्रकार क्लीन चिट दी जा रही हैं। निष्पक्ष पड़ताल के लिए यह जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में की जानी चाहिए, जिसमें सशस्त्र बल, नौसेना, मिलिटरी इंटेलिजेंस, आईबी एवं अन्य स्पेशियलाईज्ड एजेंसियों से भी सदस्य हों।

प्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री को देश को भरोसे में लेकर बताना होगा कि वो समुद्री तट की रक्षा किस प्रकार करेंगे और यह विश्वास दिलाना होगा कि छः 'Scorpene पनडुब्बियों' के निर्माण के 'प्रोजेक्ट 75' से पूरी तरह से समझौता नहीं किया गया है और हमारी तटरेखाओं को दुश्मन पड़ोसियों के सामने कमजोर नहीं कर दिया गया है, अन्यथा इन पनडुब्बियों के अधिग्रहण का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री को देश को यह भी बताना होगा कि फ्रांसीसी कंपनी के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी, जो लीक के लिए भारतीय प्रतिष्ठान को दोषी ठहरा रही है एवं 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड आउटफ्लो के साथ जनता की गाढ़े पसीने की कमाई की रक्षा किस प्रकार की जाएगी।

रक्षामंत्री श्री मनोहर पार्रिकर इन जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्हें लीक की इस बड़ी गलती के लिए राजनैतिक कार्यकारिणी, ब्यूरोक्रेट्स एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी ही पड़ेगी, जिसके चलते देश की सुरक्षा को कभी न भरने वाला घाव लगा है।